



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 67

4 Poush, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification

24th January, 2019

Notification No. 76/2018 – State Tax

S.O. No. 18 Dated- 24th January, 2019-- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)(hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department S.O. No. 77 – State Tax, dated the 13th September, 2017 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department S.O. No. 121 – State Tax, dated the 09th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, and notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department S.O. No. 139 – State Tax, dated the 14th November, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee payable by any registered person for failure to furnish the return in FORM GSTR3B for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act, which is in excess of an amount of twenty-five rupees for every day during which such failure continues:

Provided that where the total amount of state tax payable in the said return is nil, the amount of late fee payable by such registered person for failure to furnish the said return for the month of July, 2017 onwards by the due date under section 47 of the said Act shall stand waived to the extent which is in excess of an amount of ten rupees for every day during which such failure continues:

Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said return between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.

2. This notification shall be deemed to be effective from 31st December, 2018.

[File. No Va Kar / GST / 03/ 2018]
By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,
Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

24 जनवरी, 2019

अधिसूचना सं०. 76/2018- राज्य कर

एस. ओ. सं. 18 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड - सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 77, तारीख 13 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 121, तारीख 9 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित, झारखण्ड सरकार के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना एस. ओ. सं. 139, तारीख 14 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय राज्य कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख

तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है।”।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2018 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वांकर/जी०एस०टी०/03/2018]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव-सह-आयुक्त
